राष्ट्रीय हिंदी, साप्ताहिक खबरें

जनती की समस्या, हर पल टाइम्स की खबर

HAR PAL TIMES

हर पल टाइम्स

RNI No. : MAHHIN/2011/24374

कार्यकारी संपादक : जमील जी. खान

वर्ष : ११ अंक : १९ मुंबई, शुक्रवार, ७ ज़नवरी से १३ जनवरी २०२२ पृष्ठ : ४ मुल्य : रू. २/-

मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखंड, चेन्नई, कलकत्ता जानेवाला अखबार (०७४९८५३५२८६ आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करे)

फिलहाल 100 फीसदी लॉकडाउन की जरुरत नहीं : स्वास्थ्य मंत्री टोपे

मुंबई (संवाददाता) : कोविड-१९ के बढते मामलों के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि फिलहाल १०० फीसदी लॉकडाउन की जरुरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पाबंदियां लगाने की जरुरत पर बल दिया।

राज्य के कोविड-१९ कार्यबल और राज्य के स्वास्थ्य, योजना और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में टोपे ने कहा कि मंगलवार को राज्य में १६,००० से ज्यादा नये मामले आए थे और बुधवार को यह संख्या बढकर २५,००० हो गई।

उन्होंने कहा कि इसमें बडी बात यह है कि ९० फीसदी मामलों/मरीजों में बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ १० फीसदी मरीजों में लक्षण नजर आ रहे हैं और उनमें से भी महज दो प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरुरत है।

पिछले दो सप्ताह से राज्य में कोविड-१९ के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है।

मंत्री ने कहा, "कार्यबल ने पाबंदियों में वृद्धि शब्द का उपयोग किया है, इसका अर्थ है, अगर मामलों में ऐसे ही वृद्धि होती रही.... हमें अभी लॉकडाउन का उपयोग नहीं करना है। आज की बात करें तो १०० फीसदी लॉकडाउन की जरुरत नहीं है।"

उन्होंने कहा कि वृद्धि संबंधी पाबंदियां लगाने से सिर्फ गैर-जरुरी गतिविधियों पर रोक लगेगी।

टोपे ने कहा, "जहां-जहां भीड़ होती है, वहां पाबंदियां लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर पाबंदियां लगायी जाएं।" उन्होंने कहा कि कार्यबल की सिफारिशों पर (पृष्ठ 2 पर)

पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताई चिंता, मिलने पहुंचे नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर चिंता जाहिर की है। यही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी खुद कुछ देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने पंजाब में हुए घटनाक्रम को लेकर चिंता व्यक्त की है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। इसके अलावा सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग भी इस मसले पर बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और घटना को लेकर चर्चा हुई।

पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली में जाने वाले थे। इस रैली में वह ४२,७५० करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ऐलान करने जा रहे थे, लेकिन उनका एक काफिला फ्लाईओवर पर २० मिनट तक फंसा रहा। यह घटना किसानों के एक संगठन की ओर से प्रदर्शन के चलते हुई। पीएम मोदी के काफिले के फंसने को सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला माना गया और इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस की पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। इससे पहले गुरुवार को सुबह (पृष्ठ 2 पर)

पीएम की सुरक्षा में चूक की हो न्यायिक जांच, नवाब मलिक की मांग

मुंबई (संवाददाता) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने टिप्पणी की है। मलिक ने कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह मामला गंभीर है, इसकी न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य को इसकी जांच खुद करने से बचना चाहिए वरना संदेह पैदा होगा।

कुर्ला एल विभाग का होगा विभाजन

एल-नॉर्थ, एल-साउथ नए दो डिवीजन; समूह नेताओं की बैठक में प्रस्ताव

मुंबई (संवाददाता) : नगर पालिका के कुर्ला एल संभाग की जनसंख्या ८ लाख ९९ हजार ४२ होने के कारण यहां अधोसंरचना पर जोर है। इसलिए मुंबई नगर निगम ने इस विभाग को बांटने का फैसला किया है। दो खंड, एल-उत्तर और एल-दक्षिण बनाए जाएंगे। प्रशासन ने प्रस्ताव को समूह नेताओं की बैठक में मंजूरी के लिए रखा है। इस संभाग में १६ वार्ड हैं और इन वार्डो को विभाजित कर संभागीय कार्यालय बनाए जाएंगे। एक मंडल में ९ व दूसरे संभाग में ७ वार्ड शामिल होंगे। एल-उत्तर डिवीजन में १५६ से १६४ वार्ड और एल-दक्षिण डिवीजन में १६५ से १७१ वार्ड शामिल किए जाएंगे।

एल-उत्तर मंडल कार्यालय चांदीवली उप मुख्य अभियंता (भवन प्रस्ताव) विशेष कक्ष, एम. सी. एम. सी. आर. इस कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। एल-दक्षिण कार्यालय वर्तमान संभागीय कार्यालय लक्ष्मणराव यादव मंडई स.गो.बर्वे मार्ग कुर्ला पश्चिम में रहेगा। दोनों संभागों के लिए अलग-अलग वार्ड कमेटी बनेगी। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि इन दोनों विभागों को उपायुक्त परिमंडल ५ में शामिल किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे पर जोर

मुंबई नगर निगम के कुछ विभागों की आबादी ९ से १० लाख तक पहुंच गई है, इसलिए इन विभागों को चरणों में बांटा जाएगा। सबसे अधिक मलिन बस्तियों में बसे कुर्ला एल संभाग में आबादी लगभग ८ लाख ९९ हजार तक पहुंचने के साथ, संभाग कार्यालय के लिए नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मुश्किल होता जा रहा है। विभाग में व्यवस्था भी चरमरा रही है।

प्राइवेट अस्पतालों को बूस्टर डोज देने की अनुमति! मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग

मुंबई : राज्य में कोरोना मरीजों की बढती संख्या के बावजूद राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, बढती भीड़ और मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों को और कड़ा करने का फैसला लिया है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई, जो तकरीबन एक घंटे चली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव और मुख्य सचिव भी शामिल थे। बैठक में राज्य की ताजा स्थिति की समीक्षा की गई और फैसला लिया गया कि इस समय राज्य में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, प्रतिबंधों को कडा करने का निर्णय लिया (पृष्ठ 3 पर)

।। निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की आवश्यकता ।।

संपादकीय

सुरक्षा से समझौता

प्रधानमंत्री का काफिला अगर किसी फ्लाईओवर पर १५-२० मिनट के लिए रुक जाए, तो यह न सिर्फ चिंता की बात, बल्कि गंभीर लापरवाही का प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, उन्हें फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन जब काफिला रुक गया, तो उन्हें लौटना पड़ा। विशेषज्ञ इसे सुरक्षा में भारी चूक मान रहे हैं। पंजाब पहले आतंकवाद की जमीन रह चुका है, अत: वहां विशिष्ट लोगों की सुरक्षा चाक-चौबंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो विशेष रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन पंजाब में यह शायद सरकार के स्तर पर हुई बड़ी चूक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और राज्य सरकार ने भी तत्काल कदम उठाते हुए फिरोजपुर के एसएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंजाब सरकार को इस चूक की तह में जाना चाहिए। अगर यह चूक प्रशासन के स्तर पर हुई है, तो ऐसे लापरवाह अधिकारियों के लिए सेवा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और यदि इसके पीछे कोई सियासत है, तो इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता। प्रदर्शनकारियों को पता था कि प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, लेकिन क्या यह बात सुरक्षा अधिकारियों को नहीं पता थी कि प्रधानमंत्री का रास्ता प्रदर्शनकारी रोकने वाले हैं?

यह बात कतई छिपी नहीं है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां दुश्मन तत्वों की सक्रियता अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे तत्वों के साथ अपराधी तत्वों का घालमेल हमें पहले भी मुसीबत में डाल चुका है। बेशक, इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री से कुछ मांगने का पूरा हक है, लेकिन उनका रास्ता रोकने की हिमाकत किसी अपराध से कम नहीं है। गया वह जमाना, जब प्रधानमंत्री की लोगों के बीच सहज उपस्थिति संभव थी, अब पहले जैसा खतरा हम नहीं उठा सकते। क्या हमने एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोकर कुछ सीखा है? दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक बैठने और पंजाब में सीधे प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के बीच जमीन-आकाश का फासला है।

अब इसमें शक नहीं कि राजनीति तेज हो जाएगी, क्योंकि पंजाब में हुई इस चूक ने मौका दे दिया है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने भी इस चूक पर नाराजगी जताई है। अत: इस चूक को पूरी गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उस राज्य में रास्ता रोकने की राजनीति अपनी हदों में रहे। ऐसे रास्ता रोकने की दुष्प्रवृत्ति पर तत्काल प्रहार की जरूरत है, ताकि आगे के लिए एक मिसाल बन जाए। आशंका है कि ऐसे रास्ता रोकने वालों को किसी प्रकार की कार्रवाई से बचाने के लिए भी पंजाब में राजनीति होगी। कोई आश्चर्य नहीं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की खबर के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। गंभीर राजनीति को ठोस समाधान के बारे में सोचना व बताना चाहिए, राष्ट्रपति शासन समाधान नहीं है। यह दु:खद है कि अपने देश में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच अक्सर समस्या जस की तस बनी रह जाती है। अपना तात्कालिक राजनीतिक मकसद हल करने के बाद नेता भी ऐसी मूलभूत चूक या समस्या को भुला देते हैं। इस बार ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। उम्मीद कीजिए, पूरा सच और समाधान सामने आएगा।

बुली बाई ऐप मामले में एक और स्टूडेंट गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की कार्रवाई, मास्टरमाइंड की तलाश जारी

मुंबई : बुली बाई एप मामले में मुंबई पुलिस ने एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने इस स्टूडेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इस मामले पर बुधवार दोपहर मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नागराले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक का नाम शुभम रावत बताया जा रह है। जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कोटद्वार क्षेत्र के निम्बूचौड़ इलाके का रहने वाला है। शुभम रावत दिल्ली में पढ़ाई करता है।

बेंगलुरु से गिरफ्तार विशाल कुमार को मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने १० जनवरी तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है वहीं उत्तराखंड से गिरफ्तार महिला को भी मुंबई लाने का प्रयास शुरु है।

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि दोनों ही आरोपी यानी २१ वर्षीय छात्र और महिला एक दूसरे को जानते थे। आरोपी महिला बुली एप से संबंधित तीन अकाउंट चलाती थी। इस मामले में सह आरोपी विशाल ने सबसे पहले खालसा सुपरमसिस्ट नाम से अकाउंट खोला था। जांच में यह भी पता चला कि ३१ दिसंबर को विशाल ने बाकी अकाउंट के नाम भी बदल दिए थे। जिससे यह लगे कि यह सिख नाम से संबंधित अकाउंट है। हालांकि बाद में पता चला कि ये सभी फेक खालसा अकाउंट होल्डर के नाम हैं। उत्तराखंड से हिरासत में ली गई इस महिला को ट्रांजिट रिमांड के बाद क्राइम ब्रांच मुंबई लेकर आएगी। इस बात की भी संभावना है कि दोनों ही आरोपियों को मुंबई पुलिस आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी।

ऐप में मुस्लिम महिलाओं की बोली

गौरतलब है कि बुली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें लगाकर उनकी कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है। इस मामले में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत पर पश्चिम प्रादेशिक क्षेत्र साइबर पुलिस ने गिटहब पर होस्ट किए गए 'बुल्ली बाई' ऐप डिवेलपर के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया था।

मुंबई जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर लापता, दफ्तर में लंच करके टहलने निकले थे अधिकारी

मुंबई : माल एंव सेवा कर (जीएसटी) के एक अधिकारी गुरुवार को लापता हो गए। वह लंच करके टहलने निकले थे लेकिन दफ्तर नहीं पहुंचे। ५५ वर्षीय जॉइंट कमिश्नर के अचानक लापता होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

अधिकारी के लापता होने की जानकारी उनके कार्यालय के सचिव ने बुधवार को दी। पुलिस ने बताया कि जॉइंट कमिश्नर मझगांव इलाके में अपने कार्यालय से लापता हो गए। दोपहर के भोजन के बाद, वह टहलने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। सहयोगियों ने बताया कि पहले तो उसके साथियों ने सोचा कि वह किसी से मिलने गए होंगे, लेकिन शाम तक नहीं लौटने पर लोगों को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस के अनुरोध पर अधिकारी का नाम रोक दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अधिकारी के मोबाइल पर जब कॉल की गई तो वह दफ्तर में ही मिला। पुलिस ने अधिकारी की सीडीआर निकलवाई है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि अधिकारी की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। लापता अधिकारी के परिवार ने अपने रिश्तेदारों से भी पूछताछ की कि कहीं वह किसी से मिलने तो नहीं गए लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह अपहरण का मामला है या वह खुद कहीं चले गए हैं। सीडीआर की जांच और सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिलने के बाद ही कुछ स्थिति साफ हो सकेगी।

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, 13 मंत्री... (पृष्ठ 4 का शेष)

सामने आए। अब तक ओमीक्रोन के ६५३ मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमीक्रोन के नये मामलों में ४० मामले राजधानी मुंबई से सामने आए।

मुंबई में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के १०,८६० नये मामले सामने आए। पिछले दिन के मुकाबले संक्रमण के नये मामलों में ३४.३७ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। संक्रमण के दैनिक मामलों की यह संख्या सात अप्रैल २०२१ के बाद सबसे अधिक है। मुंबई में बीते २४ घंटे के दौरान महामारी से दो मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर ८,१८,४६२ हो गयी है। अब तक कुल १६,३८१ मरीजों की मौत हो चुकी है।

फिलहाल 100 फीसदी लॉकडाउन की... (पृष्ठ 1 का शेष)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राय ली जाएगी। मंत्री ने टीकाकरण पर जोर दिया और कहा कि जिन्होंने अभी भी टीका नहीं लगवाया है, उन्हें तत्काल इंजेक्शन लेने और कोरोना योद्धाओं को तीसरी खुराक लगाए जाने की जरूरत है।

पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में... (पृष्ठ 1 का शेष)

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा पंजाब सरकार की ओर से सुरक्षा में चूक की जांच के लिए एक हाईलेवल कमिटी के गठन का भी फैसला लिया गया है।

इस बीच सुरक्षा चूक की घटना की जांच के लिए बनी समिति के मुखिया ने भी मामले को गंभीर बताया है। पंजाब सरकार की ओर से गठित समिति के मुखिया जस्टिस मेहताब सिंह गिल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला बेहद गंभीर है। इस मामले पर विस्तार से बोलने से इनकार करते हुए मेहताब सिंह गिल ने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है। प्रथमदृष्ट्या ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चूक हुई है। किसी की भी जिम्मेदारी तय करने से पहले हम इस चूके बारे में पता लगाने का प्रयास करेंगे।' पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमिटी गठित की और तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

उपनगरीय ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध की फिलहाल कोई योजना नहीं: बीएमसी

मुंबई (संवाददाता) : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढते मामलों के बीच मुंबई एक वरिष्ठ नगर निकाय अधिकारी ने बताया कि मुंबई में उपनगरीय ट्रेन यात्रा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि शहर में कोविड-१९ के दैनिक मामलों की संख्या और लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर बढ.रही है और बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है तथा हर प्रकार के संकट से निपटने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि उपनगरीय ट्रेन यात्रा पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन यदि जरूरत पडती है तो महाराष्ट्र सरकार कोविड-१९ संबंधी राज्य कार्य बल के परामर्श से इस मामले पर निर्णय लेगी क्योंकि यह पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) से संबंधित मामला है।

काकानी ने कहा कि इस समय कोरोना वायरस के ९० प्रतिशत मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं है और केवल चार से पांच प्रतिशत मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है और गंभीर संक्रमण के मामलों की संख्या नगण्य है।

उन्होंने कहा, ''मुंबई के अस्पतालों में ३०,५०० बिस्तरों में से केवल ३,५०० बिस्तरों पर मरीज हैं। इसके अलावा, ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाएं, वेंटिलेटर, आईसीयू सुविधाएं और अस्पताल के बिस्तर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।''

मुंबई में सोमवार को कोविड-१९ के ८,०८२ नए मामले सामने आए जो १८ अप्रैल, २०२१ के बाद से सर्वाधिक दैनिक संख्या है। इसके अलावा शहर में सोमवार को संक्रमण के कारण दो लोगों की मौत हुई।

गोवा से लौटे क्रूज पोत पर 139 और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि

मुंबई : गोवा से मुंबई लौटे कॉर्डेलिया क्रूज पोत पर सवार १,८२७ यात्रियों में से १३९ और यात्री बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। यह जानकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने दी। ये संक्रमित उन ६६ यात्रियों के अलावा हैं जिनमें पूर्व में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ६६ में से ६० यात्री मुंबई लौट आए जबकि छह गोवा में उतरे।

बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि जिन यात्रियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हें घर पर ही पृथक-वास में रखा जाएगा, जबकि लक्षण वाले यात्रियों को संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा। इससे पहले, बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मंगला गोमारे ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया था कि १४३ यात्री कोविड-१९ से ग्रस्त हैं लेकिन देर रात महानगरपालिका ने इन आंकडों को संशोधित कर १३९ कर लिया। गौरतलब है कि पोत के दक्षिण मुंबई के बलार्डपियर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर पहुंचने के बाद बीएमसी ने उस पर सवार १,८२७ यात्रियों के नमूने एकत्रित किए थे।

कांग्रेस अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव : जगताप

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस आगामी बृहमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव में अकेले सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस की शहर इकाई के अध्यक्ष भाई जगताप ने मंगलवार को यह बात कही। जगताप ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित बीएमसी चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी रैली करेंगे। कांग्रेस के १३७वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित काग्रक्रम के दौरान जगताप ने कहा, ''बीएमसी के आगामी चुनाव में कांग्रेस सभी २३६ सीटों पर अकेले चुनाव लडेग़ी और एक बार फिर बीएमसी में कांग्रेस का झंडा फहराएगी।'' इस मौके पर शहर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि ''हम सभी सीटों पर लडेग़े और जीतेंगे।''

प्राइवेट अस्पतालों को बूस्टर... (पृष्ठ 1 का शेष)

गया, ताकि बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़-भाड़ को रोका जा सके। इस दौरान कंटेनमेंट जोन के विस्तार, टीकाकरण में तेजी, अस्पतालों की तैयारी आदि की भी समीक्षा की गई। इस बैठक की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी जाएगी।

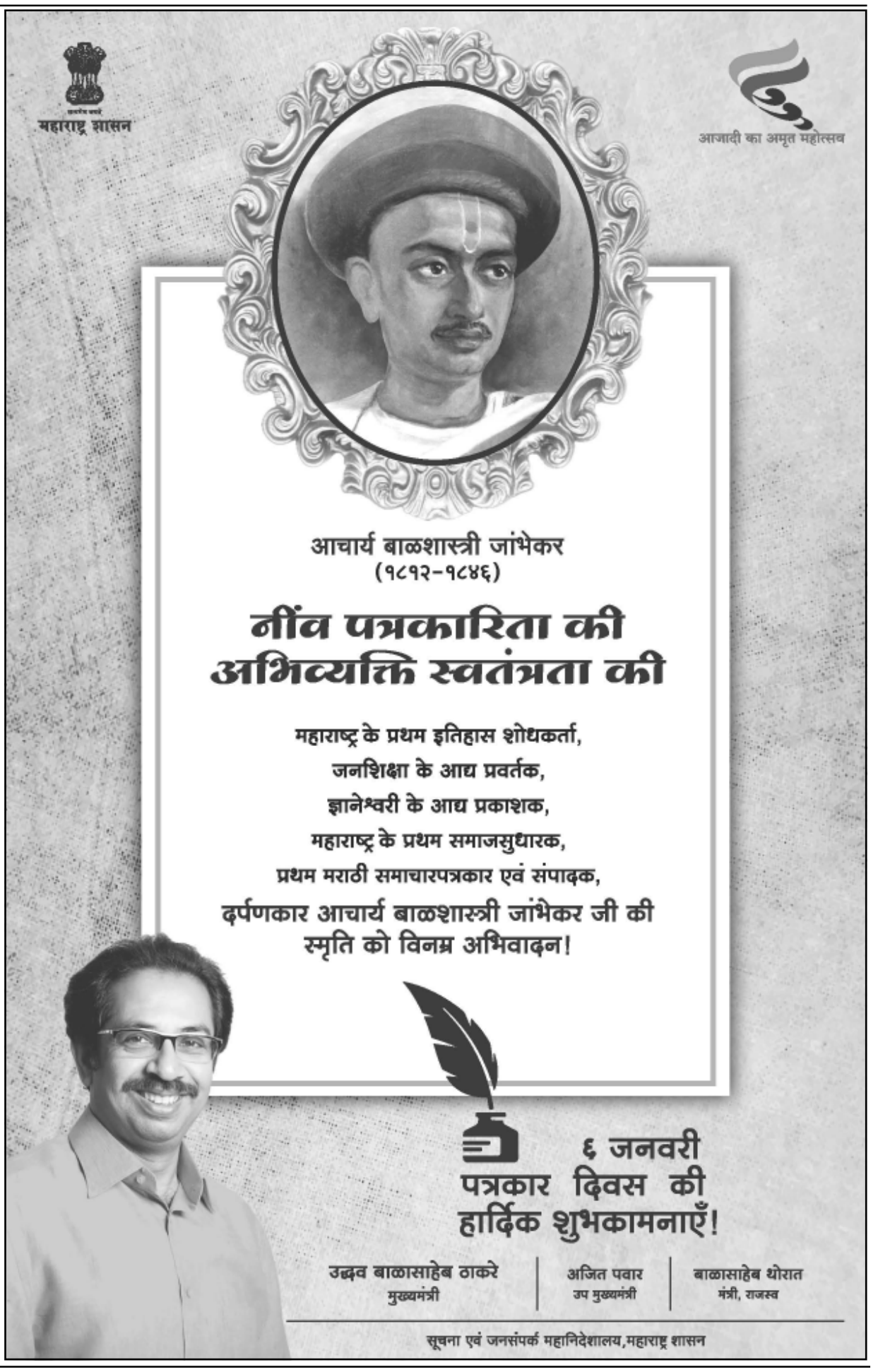

दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के संकेत! मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है फैसला

मुंबई (संवाददाता) : राज्य सरकार के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक सरकार के भीतर वीकेंड लॉकडाउन लगाने को लेकर गंभीर विचार मंथन चल रहा है। खबर है कि संपूर्ण लॉकडाउन के मुद्दे पर नेताओं और अधिकारियों के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। नेता लॉकडाउन लगाने के खिलाफ हैं जबकि अधिकारियों का कहना है कि या तो कड़क प्रतिबंध लगाए जाएं या मिनी लॉकडाउन लगाया जाए। इन हालात में अब फैसला मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को लेना है।

प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव है कि यदि एक-दो दिन में ही फैसला नहीं लिया, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। जबकि नेताओं का कहना है कि हर जिले की स्थिति अलग अलग तरह से प्रभावित हो रही है इसलिए हर जिले के लिए प्रतिबंध अलग-अलग तरह के होने चाहिए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है और बाकी दिनों के लिए प्रतिबंधों को सख्त किए जाने की बात की जा रही है।

मंत्रिमंडल की बैठक में होगी कोरोना की समीक्षा : राज्य में तेजी से पैर पसारते ओमिक्रोन वेरिएंट के संक्रमण के बीच बुधवार को सुबह ९:०० बजे होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। बता दें कि तेजी से फैलते संक्रमण के चलते मुंबई ठाणे समेत कई महानगरपालिका क्षेत्रों में स्कूल ३१ जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है राज्य में फिर से लॉकडाउन की अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य के सिर्फ ४ जिलों में संक्रमण की रफ्तार तेज है। इसलिए पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सारी स्थिति पर विचार किया जाएगा।

चांदीवली के काजूपाडा स्थित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मैदान में मनपा और उपयुक्त युवा समाजसेवा संगठन द्वारा आयोजित फ्री टीकाकरण कैम्प का उद्घाटन आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया। इस मौके पर संस्थापक अध्यक्ष मोहसिन शेख, एनसीपी नेता बाबू बत्तेली, एड कैलास आगवने, रत्नाकर शेट्टी और अन्य मान्यवर उपस्थित थे।

कोरोना के १० से ज्यादा मामले आये तो पूरी बिल्डिंग होगी सील

कोविड-19 से निपटने के लिए बीएमसी ने अपने प्लान में किया संशोधन

मुंबई : ओमीक्रोन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने बिल्डिंग सील करने के प्रोटोकॉल में संशोधन किया है। बीएमसी के नए सर्कुलर के अनुसार, किसी बिल्डिंग के विंग, कॉम्प्लेक्स या सोसायटी के कुल फ्लैट के २० प्रतिशत फ्लैट में यदि कोरोना के १० मामलों की पुष्टि होती है तो तो पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा।

बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार

पेशंट व उसके कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों को कड़ाई से प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना पेशेंट को १० दिन तक आइसोलेटेड रहना अनिवार्य किया गया है।

इसी तरह, हाई रिस्क वाले लोगों को ७ दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा। ५वें व ७वें दिन उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा। सोसायटी मैनेजिंग कमिटी क्वारंटीन परिवार के लिए राशन, दवाई व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगी। बिल्डिंग को सील करने की प्रक्रिया वॉर्ड स्तर पर होगी। कोरोना को लेकर मेडिकल ऑफिसर या वॉर्ड ऑफिसर द्वारा जारी प्रोटोकॉल व कंटेन्मेंट के नियमों का लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा।

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, 13 मंत्री और 70 विधायक पॉजिटिव, 24 घंटे में आये 18,466 नये मामले, 20 की मौत

मुंबई (संवाददाता) : महाराष्ट्र में अब तक १३ मंत्री और ७० विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री और शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे, सांसद अरविंद सावंत, आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई और युवा सेना के सचिव वरुण देसाई और विधायक प्रताप सरनाईक को भी कोरोना हो गया है। कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार के अनुसार राज्य के १३ मंत्री और ७० विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले राज्य के मंत्रिमंडल के १० मंत्री और २० विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दी थी।

महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तमाम प्रयासों के

बाद भी इसकी रफ़्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में मंगलवार को को कोरोना वायरस संक्रमण के १८,४६६ नये मामले सामने आये जबकि २० लोगों की मौत हो गयी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अभी भी ३९ हजार से ज्यादा मरीज होम क्वांरटीन हैं जब की ११ से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि नये मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर ६७,३०,४९४ हो गयी है जबकि मरने वालों की संख्या १,४१,५७३ हो गयी है। महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के ७५ नये मामले (पृष्ठ 3 पर)

मुंबई में कम नहीं पड़ेगी ऑक्सिजन, 'दूसरी लहर से तीन गुना ज्यादा की व्यवस्था'

मुंबई : कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सिजन की पूरे देश में किल्लत हुई थी। कोरोना का हॉटस्पॉट होने के बावजूद मुंबई में किसी मरीज की मौत ऑक्सिजन की कमी से नहीं हुई थी। अस्पतालों में ऑक्सिजन की

बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएमसी की तारीफ की थी। मुंबई में तीसरी लहर की आशंका के बीच आवश्यकता के अनुसार बीएमसी ने फिर ऑक्सिजन आपूर्ति की व्यवस्था की है।

बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि हमारे पास ११५० मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजन की व्यवस्था है। हमारी तैयारी ६९० मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सिजन आपूर्ति की है, जो कोरोना की दूसरी लहर से लगभग तीन गुना ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर में पीक के दौरान प्रतिदिन २१०-२३५ मीट्रिक टन ऑक्सिजन की आवश्यकता पड़ती थी। उन्होंने बताया कि विभिन्न अस्पतालों व जंबो सेंटर में कुल ४३ ऑक्सिजन प्लांट लगाने की बीएमसी की योजना है, जिनमें ३० प्लांट लग चुके हैं, बाकी १० भी जल्द लग जाएंगे।

मालक, मुद्रक, प्रकाशक **वसिम जे. खान** ने शिरनाजी प्रिंट, एम.एल. कॅम्प, चेंबूर, मुंबई-४०० ०८९ से छपवाकर, प्लॉट नं. २५/डी/१, शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई-४०० ०४३ से प्रकाशित किया। संपादक : **वसिम जे. खान** (मो. ७०२१४२५४४२) **RNI No. : MAHHIN/2011/24374**
E-mail : harpaltimes.press@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित लेखों एवं खबरों से संपादक एवं संचालक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी विवाद के लिए न्यायकक्ष मुंबई होगा।)

राष्ट्रीय हिंदी, साप्ताहिक खबरें

जनता की समस्या, हर पल टाइम्स की खबर

HAR PAL TIMES

हर पल टाइम्स

RNI No. : MAHHIN/2011/24374

कार्यकारी संपादक : जमील जी. खान

वर्ष : ११ अंक : २२ मुंबई, शुक्रवार, २८ ज़नवरी से ३ फरवरी २०२२ पृष्ठ : ४ मुल्य : रू. २/-

मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखंड, चेन्नई, कलकत्ता जानेवाला अखबार (०७४९८५३५२८६ आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करे)

महाराष्ट्र में पिछले दो साल में उल्लेखनीय कार्य हुआ : कोश्यारी

मुंबई : महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार को कहा कि पिछले दो साल में राज्य में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। राज्यपाल ने ७३वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए अपने भाषण में, राज्य को 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' में मिले पुरस्कार और इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र में पिछले ढाई साल में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।'

गौरतलब है कि कोश्यारी और राज्य की महा विकास आघाडी सरकार के बीच रिश्ते तल्ख रहे हैं और अतीत में मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर पत्र के माध्यम से तकरार देखने को मिली है। राज्यपाल ने कुछ महीने पहले स्कॉटलैंड में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में महाराष्ट्र को मिले 'प्रेरणादायक क्षेत्रीय नेतृत्व' पुरस्कार के बारे में कहा।

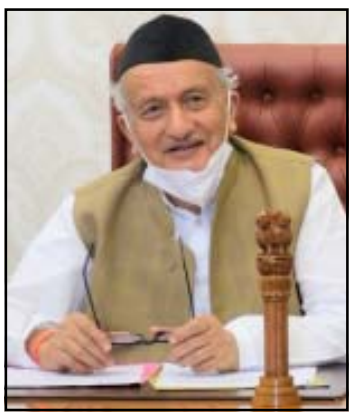

उन्होंने कहा, ''हमारे पास सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण को पूरा करने का लक्ष्य है। 'बेस्ट' इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही मुंबई में चल रही हैं।'' उन्होंने कहा कि राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वालों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है।

उन्होंने कहा, 'कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में सफलतापूर्वक योजना बनाने के लिए मुंबई मॉडल की उच्चतम न्यायालय ने सराहना की है। नीति आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस मोर्चे पर महाराष्ट्र के प्रयासों की प्रशंसा की है।' राज्यपाल ने कहा कि (महामारी के दौरान) पिछले दो साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को गिरने या रुकने नहीं दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे की जमानत याचिका खारिज की, १० दिन में सरेंडर करने का दिया आदेश

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विधायक बेटे नितेश राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोंकण की स्थानीय अदालत से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एंटीसिपेटरी बेल के लिए दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्हें १० दिन के भीतर जिला न्यायालय में सरेंडर करने का भी आदेश दिया है।

आपको बता दें कि हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले में सह-आरोपी मनीष दलवी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। इस मामले में राज्य सरकार ने तब अदालत में कहा था कि आगामी २७ जनवरी तक वे नितेश राणे के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

क्या है मामला

बीजेपी विधायक नितेश राणे पर सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना के कार्यकर्ता संतोष परब के ऊपर कथित तौर पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस मामले में सिंधुदुर्ग जिले में कनकवली पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा ३०७ (हत्या के प्रयास) के तहत नितेश राणे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका को इसके पहले भी खारिज किया जा चुका है। दरअसल जब नितेश राणे ने सिंधुदुर्ग की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। तब वहां भी अदालत ने इसे खारिज किया था। उसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय से भी निराशा हाथ लगी थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

मुंबई में एसआरपीएफ के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जान दी

मुंबई : दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके में मंगलवार को राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) के ३६ वर्षीय जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार कर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना एक सरकारी स्कूल में सुबह नौ बजकर ५० मिनट के करीब हुई, जहां जवान पुष्कर शिंदे संतरी के रूप में तैनात था। उन्होंने बताया कि शिंदे की इलाज के दौरान सरकारी जे. जे. अस्पताल में मौत हो गई।

पुणे में एसआरपीएफ ग्रुप नंबर-२ से जुड़े शिंदे छह जनवरी से यहां मंत्रालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हैं। ड्यूटी खत्म करने के बाद वह बृहन्मुंबई महानगर पालिका

के एक स्कूल गए थे, जहां वह बतौर संतरी तैनात थे।

अधिकारी ने बताया कि शिंदे स्कूल के एक कमरे में अकेले थे, जब उन्होंने अपनी एसएलआर राइफल से अपनी गर्दन पर खुद को गोली मार ली। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। शिंदे के यह कदम उठाने के पीछे के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

दुनिया में महाराष्ट्र महिलाओं के रक्षक के रूप में जाना जाएगा : मुख्यमंत्री

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि राज्य को भारत समेत पूरी दुनिया में महिला 'रक्षक' के रूप में जाना जाए। मुख्यमंत्री मुंबई पुलिस की ओर से महिलाओं की रक्षा के लिए 'निर्भया स्क्वाड' एवं निर्भया सशक्तीकरण केंद्र की शुरूआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से बोल रहे थे। इस दौरान ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा से महिलाओं को पूजता आया है और उन्हें सम्मान देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने पर काम करेगी कि महाराष्ट्र ना केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के रक्षक के रूप में जाना जाए। महाराष्ट्र एक शक्ति पूजक (महिलाओं की पूजा करने वाला) राज्य है।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्भया स्क्वाड विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं की रक्षा करनी होगी और पुलिस बल को मजबूत करना होगा। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आंकडों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं जो चिंता

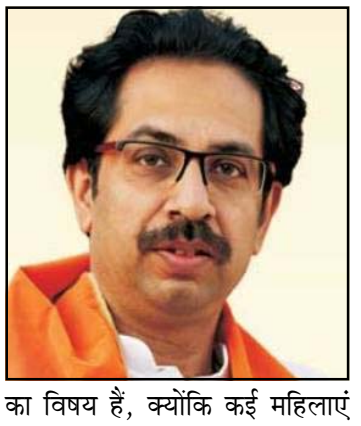

का विषय हैं, क्योंकि कई महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हैं।

पाटिल ने यह भी कहा कि लगभग ८० से ९० फीसदी घटनाओं में आरोपी पीडित महिलाओं के परिवार के परिचित होते हैं। लेकिन यह दर्शाया गया है कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है और मुंबई महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। पाटिल ने कहा कि इस तरह के चित्रण से पुलिस की छवि खराब होती है।

।। निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की आवश्यकता ।।

संपादकीय

सम्मान की गूंज

देश की मजबूती के लिए देश की कारगर प्रतिभाओं का सम्मान जरूरी है, ताकि समाज में आचरण और कर्म का एक आदर्श बना रहे। इस वर्ष देश की १२८ विभूतियों को पद्म सम्मान की घोषणा हुई है, जिनमें से चार विभूतियों को पद्म विभूषण मिलना है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, संगीतज्ञ प्रभा अत्रे के साथ ही गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को भी दिया गया सम्मान स्वागत के योग्य है। १७ विभूतियों को पद्म भूषण और १०७ को पद्मश्री की घोषणा हुई है। सीईओ सुंदर पिचई से लेकर अभिनेता विक्टर बनर्जी तक एक से बढ़कर एक हस्तियां हैं, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सरकार ने इस बार भी किसी को भारत रत्न देने की घोषणा नहीं की है, तो कोई अचरज की बात नहीं, बल्कि यह दुखद संकेत भी है कि अपने देश में सम्मान भी विवाद का विषय हुआ करते हैं। सम्मान की खुशी के साथ छटांक भर दुख या नाराजगी भी हर बार आ ही जाती है। गौर करने की बात है कि सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेब भट्टाचार्य समेत तीन हस्तियों ने सम्मान लेने से मना कर दिया है। यह संयोग ही है कि ये तीनों हस्तियां पश्चिम बंगाल से आती हैं। लगता है, वामपंथी नेता बुद्धदेब भट्टाचार्य ने राजनीतिक मतभेद की वजह से ही सम्मान लेने से मना किया है। राजनीतिक पार्टियां तो सत्ता में आती-जाती रहती हैं, दस्तावेजों पर तो यही लिखा मिलता है कि फलां वर्ष में फलां विभूति को फलां पद्म सम्मान मिला था। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, सम्मान लेने के बाद भी वह जारी रह सकता है। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, तो जरूरी नहीं कि इस अवसर का राजनीति के लिए भी लाभ लिया जाए। अफसोस, व्यंग्य में ही सही, कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें गुलाम के बजाय आजाद रहने की नसीहत दी है। हालांकि, अनेक कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। अपने किसी नेता के सम्मान पर कम से कम किसी पार्टी के अंदर विवाद नहीं होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद को दिया गया सम्मान, एक ऐसे नेता का सम्मान है, जो अपनी लोकतांत्रिक शालीनता से हर जगह व्यावहारिक पैठ रखते हैं।

दो अन्य विभूतियों ने भी पद्म सम्मान ठुकराया है। तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी और संगीतज्ञ संध्या मुखोपाध्याय के दुख को पूरी संवेदना से समझना चाहिए। अनिंदो को सरकार से बड़े सम्मान की आशा थी, तो सरकार इस पर पहले भी बात कर सकती थी। घोषणा के बाद किसी के इनकार से बनने वाली अपमानजनक स्थिति से बचना जरूरी है। पद्म सम्मान कोई राजनीतिक पार्टी अपने बैनर तले नहीं देती है, सम्मान के साथ भारत सरकार की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। यह अधिकारियों के स्तर पर कमी है कि वे विभूतियों से आवश्यक संवाद भी नहीं बना पा रहे हैं। संगीतज्ञ ९० वर्षीया संध्या मुखोपाध्याय ने सम्मान ठुकराते हुए कहा है कि ७५ वर्ष के लंबे करियर के बाद अगर सरकार को लगता है कि वह पद्मश्री के लायक हैं, तो उन्हें यह सम्मान नहीं चाहिए। वाकई यह स्थिति नहीं बननी चाहिए थी, इससे एक खराब संदेश गया है। सम्मान देते हुए सरकारों को पूरी संवेदना और पारदर्शिता के साथ तमाम पहलुओं पर विचार करना चाहिए, ताकि प्रादेशिक या राष्ट्रीय सम्मान किसी को अपमान की तरह न महसूस हो।

हिंसक होते असंतोष के मायने

आरआरबी-एनटीपीसी के परीक्षा-परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र आंदोलित हैं। गुस्साए अभ्यर्थियों ने एकाधिक ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद विरोध-प्रदर्शन के औचित्य पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा होने लगी है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अपनी मांगें मनवाना क्या उचित है! निस्संदेह, विरोध एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा लोग अपनी शिकायत या नाराजगी जाहिर करते हैं, मगर यह भी सच है कि किसी भी हिंसक विरोध का समर्थन नहीं किया जा सकता।

दरअसल, किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनता विरोध का सहारा लेती है। यह एक ऐसा अधिकार है, जो संविधान द्वारा देश के नागरिकों को हासिल है। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है यह। जनता ने भले सरकार को चुना हो, लेकिन अगर उसे लगता है कि हुकूमत उसकी बातें नहीं सुन रही, तो वह विरोध के अपने सांविधानिक अधिकारों के तहत अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाती है।

मगर विरोध को लेकर जितनी चिंता पिछले एक दशक से देखने को मिल रही है, उतनी पहले नहीं थी। विरोध कोई आज की परंपरा नहीं है। आजादी ही हमें विरोध से हासिल हुई है। आजाद भारत में भी १९७५-७७ के आपातकाल के खिलाफ तमाम राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हुए, क्योंकि लोग सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये से नाराज थे। १९९१ में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, तब भी देश भर के छात्रों ने विरोध किया। १९९० के दशक की शुरुआत में मंदिर-मस्जिद को लेकर भी पूरे देश में विरोध चलता रहा। सीएए-एनआरसी को लेकर भी लोग उबलते रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर तो किसानों का आंदोलन एक साल तक चला। मगर पहले प्रशासन विरोध-प्रदर्शनों से विचलित नहीं होता था। आंदोलकारियों को राष्ट्रद्रोही साबित करने की जल्दबाजी नहीं होती थी। इतने सख्त हाथों से आंदोलनों को दबाने की कोशिश नहीं की जाती थी। बेशक, प्रशासन को आंदोलन से निपटने का अधिकार है, ताकि सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे या आम जनता को असुविधा न हो, लेकिन पहले के वर्षों में आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाते थे। बातचीत का दरवाजा खुला रखा जाता था। लेकिन अब इसका अभाव दिखने लगा है।

यहां यह बहस बेमानी है कि इस तरह के आंदोलन सफल नहीं होते। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ऐसे विरोध सफल हुए हैं। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध हमें आजादी की सौगात दे गया। आपातकाल के विरोध से सरकार बदली। मंडल आयोग का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक गया और अंत में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। राम मंदिर भी अपने अंजाम तक पहुंचा। किसान आंदोलन के बाद सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पडे। सीएए और एनआरसी को भी विरोध के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुलजमा, तात्पर्य यही है कि इस तरह के आंदोलन इसलिए सफल होते हैं, क्योंकि जिन मुद्दों पर ये किए जाते हैं, उनसे जनता के एक बड़े हिस्से का सरोकार जुड़ा होता है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। करीब सवा लाख पदों के लिए सवा करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, यानी एक पद पर सौ गुना आवेदन आए थे, जबकि ज्यादातर भर्तियां ग्रुप डी स्तर की थीं। यह संकेत है कि देश में जबर्दस्त बेरोजगारी है। अलग-अलग राज्यों में बेरोजगारी दर ऊंची भी है। जाहिर है, छात्र नाराज हैं। उनको लग रहा होगा कि उन्होंने शिक्षा तो हासिल कर ली है, लेकिन अब नौकरी नहीं पा रही।

इन छात्रों का आंदोलन भी सफल होता दिख रहा है। यह सही है कि विरोध का तरीका हिंसक नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी हमेशा यही कहते थे कि हिंसा से आंदोलन भटक जाता है। मगर कई बार आंदोलनों में हिंसा हो जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि इनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, तो सभी का स्वभाव एक सा नहीं होता। इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आक्रामक होते हैं और जल्द ही हिंसक हो उठते हैं। इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सभी आंदोलनकारी हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। फिर, आंदोलन जब बहुत लंबा चल जाता है और आंदोलनकारियों को लगने लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रहीं, तब उनका धैर्य चूकने लगता है। आजादी के आंदोलन में चौरीचौरा कांड हमने देखा है। किसान आंदोलन में ही २६ जनवरी, २०२१ को दिल्ली में जहां-तहां हुड़दंग मचता रहा, जिसकी चौतरफा आलोचना भी हुई।

मगर छात्रों का यह आंदोलन ज्यादा पुराना नहीं है, और वे इसलिए हिंसक हो उठे, क्योंकि उनको लगा होगा कि हिंसा से ही सरकार और मीडिया का ध्यान खींचा जा सकता है। दुर्भाग्य से, ऐसा हुआ भी। शुरुआती तीन-चार दिन इस आंदोलन की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन जैसे ही आगजनी और तोड़फोड़ हुई, सरकारों ने तत्परता दिखानी शुरू कर दी। आंदोलनकारियों को अपनी मांग मनवाने का यह शॉर्टकट तरीका लगा होगा। हालांकि, जब किसी आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं, तो उसके बहकने का खतरा ज्यादा होता है।

सवाल है कि आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? दिक्कत यह है कि जब भी विरोध-प्रदर्शन शुरू होते हैं, तब सरकारी अमला देर से पहल करता है। इसी कारण आंदोलनकारी अपना संयम खोने लगते हैं। सरकारों को यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि आक्रामक होने के बाद ही आंदोलनकारियों से बात की जाएगी, क्योंकि बातचीत ही समाधान का एकमात्र रास्ता है, इसलिए इसकी शुरुआत जितनी जल्दी होगी, विरोध-प्रदर्शन की आग उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। एक बात और, कोई भी बड़ा जन-आंदोलन दमन से नहीं दबाया जा सकता। आंदोलनकारियों पर राजद्रोह या अन्य कानूनी धाराएं लगाकर हुकूमत आग में घी डालने का काम करती है। इतिहास भी ऐसे तरीकों को गलत साबित कर चुका है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

महाराष्ट्र बीजेपी के १२ विधायकों का निलंबन असंवैधानिक

अवैध और तर्कहीन, विधानसभा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के १२ भाजपा विधायकों को जुलाई २०२१ में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव 'असंवैधानिक' और 'तर्कहीन' है। शीर्ष अदालत ने

पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित किए गए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के १२ विधायकों की याचिकाओं पर यह बात कही। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा, 'हमें इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है और जुलाई २०२१ में हुए संबंधित मानसून सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए इन सदस्यों को निलंबित करने वाला प्रस्ताव कानून की नजर में असंवैधानिक, काफी हद तक अवैध और तर्कहीन है।'

पीठ ने कहा कि इस प्रस्ताव को कानून में निष्प्रभावी घोषित किया जाता है, क्योंकि यह उस सत्र की अवधि के बाद तक के लिए था, जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जुलाई २०२१ में शेष सत्र की अवधि समाप्त होने पर और उसके बाद विधानसभा के सदस्य होने के सभी लाभों को पाने के हकदार हैं। निलंबित किए गए १२ सदस्य संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगडिया हैं। इन विधायकों ने इस प्रस्ताव को अदालत ने चुनौती दी है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पांच जुलाई, २०२१ को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ इन १२ विधायकों ने कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था। इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने पेश किया था और ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा कि एक साल के लिए विधानसभा से निलंबन निष्कासन से 'बदतर' है, क्योंकि इसके परिणाम भयानक हैं और इससे सदन में एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रभावित होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि छह महीने के भीतर एक सीट भरना वैधानिक बाध्यता है।

भीड़ ने ऑटो ड्राइवर को ... **(पृष्ठ ४ का शेष)**

भी शामिल थे। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण जांच नहीं हो रही है। समता नगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक आनंदराव हाके ने कहा, 'हमने पहले शेख पर चोरी का मामला दर्ज किया और फिर परिजनों की शिकायत पर आठ लोगों के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज किया है'।

मुंबई में जब्त हुई सात ... **(पृष्ठ ४ का शेष)**

साथियों का पता चला। इसके बाद पुलिस ने अंधेरी (पश्चिम) में एक होटल में छापेमारी की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस को (दो हजार के) नकली नोटों के सौ और बंडल मिले जिनका मूल्य दो करोड़ है। डीसीपी संग्रामसिंह निशानदार (डिटेक्शन-१) ने कहा कि जांच में पता चला कि नकली नोट छापने और उनके वितरण में एक अंतरराज्यीय गिरोह काम कर रहा था। नकली नोटों के अतिरिक्त आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, सात मोबाइल फोन, २८,१७० रुपये की असली मुद्रा और अन्य चीजें बरामद की।

अब बाजार में मिलेंगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन

नई दिल्ली : कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में 'संजीवनी' साबित हो चुके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने कोविशील्ड और कोवैक्सिन के लिए सशर्त बाजार की मंजूरी दे दी है। लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन फालो करनी होगी। हालांकि अभी इस पर फैसला आना बाकी है कि बाजार में इनकी क्या कीमत होगी? ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कोविड-१९ की इन दो प्रमुख खुराकों की बाजार में कीमत २७५ रुपए कर सकती है।

गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बडा फैसला लेते हुए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए सशर्त बाजार में मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली खबरों के मुताबिक, हाल ही में हुई एक बैठक में दोनों प्रमुख टीकों की कीमतों की कैपिग पर चर्चा की गई थी।

इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, आपातकालीन उपयोग के लिए भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन की कीमत १,२०० रूपये प्रति खुराक रखी है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत ७८० रुपए रखी है। जहां वह इन वैक्सीन की कीमतों में ही १५० रूपये का सर्विस चार्ज वसूलते हैं। सरकार इन खुराकों को थोक बाजार में २०५ रुपए में खरीद रही है। लेकिन इनकी बाजार में क्या कीमत होगी इस पर फैसला आना बाकी है। वहीं कीमतों में उचित सामंजस्य बनाए रखने के लिए सरकार कंपनी को वैक्सीन पर १५० रूपये की सर्विस चार्ज की अनुमति दे सकती है।

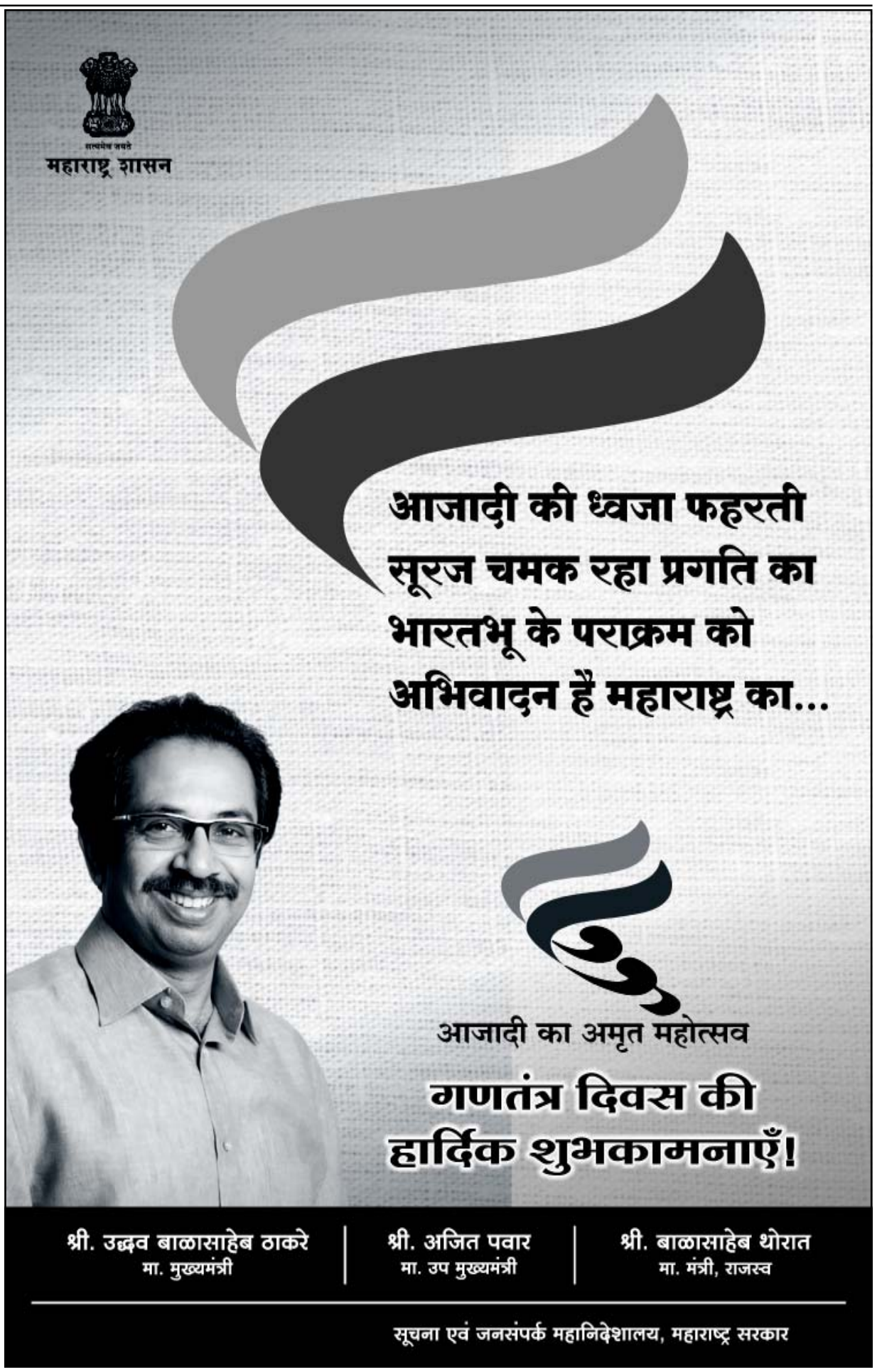

स्कूलों के बाद महाराष्ट्र में १ फरवरी से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार की मंजूरी

मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होने के साथ-साथ कुछ दिन पहले स्कूलों को खोल दिया गया था। अब राज्य सरकार ने एक फरवरी से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को भी खोलने का फैसला किया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को खोलने या न खोलने का अधिकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अलावा स्थानीय जिला प्रशासन को दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि जिन विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई हैं, उन्हीं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाए।

स्कूलों के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाने के सरकार के फैसले का शैक्षणिक जगत ने स्वागत किया है। सरकार ने इसके साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि १५ फरवरी तक आयोजित होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। इसके बाद की परीक्षाएं ऑफलाइन ली जा सकेंगी।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने आगामी २४ जनवरी से राज्य के सभी जिलों में स्कूल खोलने के आदेश जारी किए थे। दरअसल बच्चों के अभिभावकों की तरफ से यह मांग काफी समय से की जा रही थी कि स्कूलों को खोला जाए। लगातार स्कूल खोलने की बढ. रही मांग के चलते शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक प्रस्ताव भी भेजा था। जिस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी थी। अभिभावकों का यह कहना था कि जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी काफी कम हैं तो स्कूलों को खोला जाना चाहिए ताकि बच्चों की पढाई प्रभावित न हो।

क्या हैं नियम?

स्कूल खोलने के साथ महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों से यह अपील भी की है कि बच्चों को स्कूल में जबरदस्ती ना बुलाया जाए। बच्चों को स्कूल बुलाने के पहले उनके अभिभावकों की मंजूरी जरूर ली जाए। यदि अभिभावक बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल भेजना चाहते हैं तभी उन्हें स्कूल आने दिया जाए।

इसके अलावा शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ का लगवाया हुआ अनिवार्य है। साथ ही स्कूल में १५ से लेकर १८ साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रबंध भी शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर करें। इतना ही नहीं स्कूल के अधिकारियों को स्कूल खोलने के पहले तमाम जरूरी और एहतियाती कदम उठाने अनिवार्य होंगे। जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देना जरूरी होगा।

मुंबई में जब्त हुई सात करोड़ की नकली नोट, सात गिरफ्तार

मुंबई : देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए अपराधी नई-नई चलते रहते हैं। इसमें उनका एक बड़ा हथियार बन चुका है नकली नोटों का कारोबार। जाली नोटों के सौदागर देश भर में फेक करेंसी का जाल फैलाकर हिंदुस्तान कमजोर करने में लगे हुए हैं। मायानगरी मुंबई में पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने जाली मुद्रा छापने और उसे फैलाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से सात करोड़ रुपये मूल्य के नकली भारतीय नोट बरामद किये है।

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट ११ ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर शहर के दहिसर चेक नाके पर एक कार को रोका था। जब पुलिस ने गाड़ी में बैठे चार लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की और कार की तलाशी ली तो उन्हें एक बैग मिला जिसमें (दो हजार के) नकली नोटों के २५० बंडल थे। जिनका मूल्य पांच करोड़ रुपये है। कार में सवार चार लोगों से पूछताछ में पुलिस को उनके तीन और **(पृष्ठ ३ पर)**

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र पुलिस के ५१ कर्मी सेवा पदक से सम्मानित

मुंबई : केंद्र ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र पुलिस के ५१ जवानों के लिए सेवा पदक की घोषणा की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों के नाम के साथ एक सूची जारी की है।

वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक सहायक पुलिस उप-निरीक्षक गोपाल मनीराम उसेंडी, उप-निरीक्षक भरत चिंतामन नागरे, कांस्टेबल महेंद्र गानू कुलेती, संजय गणपति बकमवार, दिवाकर केसरी नरोटे, नीलेश्वर देवजी पाडा और संतोष विजय पोटवी को प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने गढचिरौली जिले में नक्सल निरोधी अभियान में भाग लिया था।

सूची के अनुसार नागरिक अधिकार संरक्षण विभाग में पदस्थापित अपर पुलिस महानिदेशक विनय करगांवकर को विशिष्ठ सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जा रहा है.

बताया गया कि एसआरपीएफ कमांडेंट प्रल्हाद खाडे, निरीक्षक चंद्रकांत गुंडगे और उप निरीक्षक अनवर बेग मिर्जा को विशिष्ट सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जा रहा है।

विशेष पुलिस महानिरीक्षक राजेश प्रधान, मीरा भयंदर पुलिस के एसीपी चंद्रकांत जाधव, वायरलेस विभाग पुणे के डीएसपी सीताराम जाधव, एसीबी, परभणी में तैनात डीएसपी भरत हुंबे, लातूर पुलिस के निरीक्षक भरत लवांडे, नवी मुंबई पुलिस के निरीक्षक अजयकुमार लांडगे और मुंबई पुलिस के जितेंद्र मिसल उन ४० अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें मेधावी सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जा रहा है।

भीड़ ने ऑटो ड्राइवर को चोर समझ पीट-पीटकर मार डाला

मुंबई : मायानगरी मुंबई के मलाड में भीड़ ने एक व्यक्ति को चोर होने की आशंका में कथित तौर पर इतना पीटा कि गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के के मुताबिक शाहरुख शेख नामक व्यक्ति को दामू नगर के लोगों ने १० दिन पहले तब पकड़ लिया था जब वह वहां पहले से खड़े अपने ऑटोरिक्शा की देखभाल करने पहुंचा था। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ ने उसे यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि वह चोर हो सकता है। भीड़ ने पिटाई करने के बाद शेख को पास के एक सूनसान जगह पर फेंक दिया था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'कुछ राहगीरों से जानकारी मिलने पर उस व्यक्ति को थाने लाया गया और उस पर चोरी का मामला दर्ज किया गया। हालांकि, आरोपी व्यक्ति को दो दिन बाद जमानत मिल गई, लेकिन संभवत: पिटाई से आई चोट के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।' मृतक के परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि वह सीसीटीवी फुटेज की पडताल कर पिटाई करने वालों को पकडे।

स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण जांच नहीं हो रही

शेख के परिजनों ने रविवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि इस घटना में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता **(पृष्ठ ३ पर)**

मालक, मुद्रक, प्रकाशक **वसिम जे. खान** ने शिरनाजी प्रिंट, एम.एल. कॅम्प, चेंबूर, मुंबई-४०० ०८९ से छपवाकर, प्लॉट नं. २५/डी/१, शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई-४०० ०४३ से प्रकाशित किया। संपादक : **वसिम जे. खान** (मो. ७०२१४२५४४२) **RNI No. : MAHHIN/2011/24374**
E-mail : harpaltimes.press@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित लेखों एवं खबरों से संपादक एवं संचालक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी विवाद के लिए न्यायकक्ष मुंबई होगा।)